अनिश्चितता में सुरक्षित निवेश है सोना

आलोक पुराणिक

सोने के भाव करीब 44००० रुपये प्रति दस ग्राम तक जा पहुंचे हैं। बीते एक साल में सोने के भावों में करीब 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। इसे बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी माना जा सकता है। इसके मुकाबले 27 फरवरी 2०2० के आंकड़ों के हिसाब से मुंबई शेयर बाजार का शेयर सूचकांक सेंसेक्स एक साल में करीब 11 प्रतिशत ही ऊपर जा पाया है। यूं 11 प्रतिशत रिटर्न एक साल में कम नहीं है, पर सोने के रिटर्न तो एक साल में करीब 27 प्रतिशत रहे हैं। यह रिटर्न देखकर कई निवेशकों के मन में यह विचार उठने लगता है कि सारी रकम सिर्फ और सिर्फ सोने में लगा देनी चाहिए। पर सोने में निवेश को लेकर कुछ बातों को समझना जरूरी है।

सोने की कीमतें तब आसमान की ओर बढ़ती हैं, जब अनिश्चितता का माहौल होता है। विश्व में इस समय एक भीषण अनिश्चितता का माहौल है, कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू तो चीन से हुआ है, पर अब इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ रही है। कई वजहों से, भारतीय उद्योग जगत भी इसकी चपेट में है। भारत के कई उद्योगों का ताल्लुक चीन से है। दवा उद्योग, मोबाइल हैंडसेट उद्योग, आटोमोबाइल उद्योग। उन उद्योगों से जुड़े कच्चे माल की सप्लाई चीन से होती है। चीन में कोरोना वायरस की वजह से तबाही फैली हुई है। माल आ नहीं आ पा रहा है तो भारतीय उद्योग जगत भी संकट में है। मुंबई शेयर बाजार के सूचकांक सेंसेक्स के उतार-चढ़ाव में भी इस संकट के खौफ को देखा जा सकता है।

ऐसी सूरत में अनिश्चितता और खौफ के चलते तमाम निवेशक शेयर आदि से अपनी रकम निकालकर सोने में डालना शुरू करते हैं। सोने को लेकर एक बात बिल्कुल पक्की है, यह अनिश्चितता के दौर में सबसे महत्वपूर्ण निवेश का माध्यम है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता है। अनिश्चितता, तनाव, युद्ध की स्थितियों में सोने के भाव इसीलिए ऊपर जाते हैं कि तमाम निवेशक सोने की तरफ दौड़ते हैं। सदियों से इसके प्रति इस कदर आकर्षण है कि लोग इसमें रकम लगाते हैं और लगाते जाते हैं। इस वजह से इसका ग्लोबल आकर्षण है। तमाम केंद्रीय बैंक सोने को खरीदकर अपने भंडार में रखते हैं, जिस केंद्रीय बैंक के पास सोने के जितने ज्यादा भंडार होंगे, उसकी स्थिति उतनी ही मजबूत मानी जायेगी। खासतौर पर संकट, अनिश्चितता, तनाव के वक्त तो सोने के भाव आसमान छू रहे हैं।

पर ऐसी सूरत में भी निवेशकों को अपनी सारी रकम सोने में नहीं लगानी चाहिए। अपने निवेश योग्य संसाधनों का एक हिस्सा ही सोने में जाना चाहिए। और अब तो सोने में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं यानी सोने में निवेश का मतलब अब यह नहीं कि सोना खरीदकर भौतिक सोना घर में रखा जाये। अब तो सोने के शेयर यानी सोने को शेयर के तौर पर खरीदने के विकल्प मौजूद हैं, इस शेयर के भाव सोने के भावों की तर्ज पर ऊपर-नीचे होते रहते हैं। भौतिक सोने में तो कई तरह के संकट होते हैं। भौतिक सोना लुट सकता है। पर सोने के शेयर के साथ यह दिक्कत नहीं है। वह तो इलेक्ट्रानिक तौर पर मौजूद होता है, जब आपको पैसे चाहिए, सोने के शेयर को बेचकर आप पैसे खरे कर सकते हैं।

ऐसा ही एक निवेश विकल्प है- एचडीएफसी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ। 27 फरवरी 2०2० को हिसाब लगायें तो इसने एक साल में 26.54 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन सालों में इसका सालाना रिटर्न रहा है-11.62 प्रतिशत। यानी छोटी अवधि में इसके रिटर्न परम शानदार रहे हैं। पर पांच सालों का हिसाब लगायें तो इसका रिटर्न रहा है-8.85 प्रतिशत सालाना और सात सालों का इसका रिटर्न रहा है-4.24 प्रतिशत सालाना। सात सालों का इसका रिटर्न आकर्षक नहीं माना जा सकता। पर बीते एक साल का इसका रिटर्न परम आकर्षक है। एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की स्कीम है। 31 जनवरी, 2०2० को इस स्कीम के पास करीब 669 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां थी। यह स्कीम मूलत- सोने में ही निवेश करती है, तो सोने के भावों के उतरने चढ़ने के साथ ही इस स्कीम की कीमतों में तेजी मंदी आती है।

कुल मिलाकर सोने को लेकर एक संतुलित रुख अपनाना जरूरी है। इसमें ही सारी रकम लगा देना ठीक नहीं है और सोने को बिल्कुल उपेक्षित करके छोड़ना भी ठीक नहीं है। निवेशकों को अपने निवेश योग्य संसाधनों का एक हिस्सा सोने में या सोने से जुड़े निवेश माध्यमों में जरूर लगाना चाहिए। दीर्घकाल में सोने के रिटर्न बहुत आकर्षक भले ही ना हों, पर यह सुरक्षित निवेश का माध्यम है।

म्यूचुअल फंड निवेश में बाजार जोखिम रहते हैं। इसलिए निवेशक अपना अध्ययन करें या किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह लें।

संपादकीय

कोरोना: अब अर्थतंत्र पर मार

कोरोना वायरस इंसानों को ही नहीं, विश्व अर्थव्यवस्था को भी बीमार कर रहा है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने पिछले सोमवार को जारी एक विशेष रिपोर्ट में कहा है कि कई देशों में कोविड-19 बीमारी फैलने से वैश्विक अर्थव्यवस्था मौजूदा तिमाही में एक बड़े झटके से गुजर सकती है, जो 2००9 में आई मंदी के बाद पहली बार होगा। हालांकि 2०2० के लिए ओईसीडी ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को करीब आधा प्रतिशत ही घटाया है, लेकिन यह भी कहा है कि यदि वायरस दुनिया में व्यापक तौर पर फैल जाता है और गर्मी में भी इसका असर बरकरार रहता है तो यह वृद्धि 2.9 प्रतिशत के अनुमान की लगभग आधी, यानी 1.5 प्रतिशत तक भी पहुंच सकती है।

विश्व बैंक पहले ही कोरोना की वजह से ग्लोबल ग्रोथ रेट में एक फीसद तक की गिरावट की आशंका जता चुका है। कोरोना की वजह से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं चीन और अमेरिका के कारोबार में सुस्ती गहरा रही है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। चीन ग्लोबल स्तर पर विभिन्न जिंसों (कमोडिटीज) का सबसे बड़ा खरीदार है। वहां मांग में कमी के कारण विश्व स्तर पर कच्चा तेल, तांबा, सोयाबीन जैसे कई उत्पाद सस्ते हो जाएंगे लेकिन जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं चीन को इन चीजों की आपूर्ति पर निर्भर करती हैं उनकी, खासकर लैटिन अमेरिका के कई देशों की हालत खराब हो जाएगी।

मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 से जुड़ी खबरों और आशंकाओं के चलते दुनिया भर का टूरिज्म प्रभावित हो रहा है। चीन का पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप है। विदेशी उड़ानें चीन नहीं जा रही हैं और करूज यात्राएं भी रद्द हैं। दूसरी तरफ 3० लाख चीनी हर साल अमेरिका घूमने जाते हैं। इटली में बीमारी फैलने से पर्यटक अब यूरोप जाने से भी कतराने लगे हैं, जिससे वहां का पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में फैक्ट्रियों के बंद होने से ऐपल, नाइकी और जनरल मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियां प्रभावित हो रही हैं।

माल की कमी के चलते अमेरिका के वॉलमार्ट और अमेजन स्टोर में अगले एक-दो महीने में सभी सामानों की कीमतें बढ़ जाएंगी। अमेरिका की विकास दर 2०2० में ०.2 फीसद की गिरावट के साथ 1.7 फीसद रहने का अनुमान है। अपना लगभग एक तिहाई व्यापार अमेरिका और चीन के साथ ही करने वाला भारत भी इस आर्थिक संकट से अछूता नहीं रहेगा।

चीन से आयात होने वाली जिन चीजों पर भारतीय उद्योग निर्भर हैं उन्हें लेकर भी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। कच्चे माल की कमी और उत्पादन लागत बढ़ने से हमारे निर्यात की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार हमारी विकास दर पर कोरोना के असर की बात करना अभी जल्दबाजी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरकार इस मामले में सतर्क है और हर स्तर पर विकल्प तलाशे जा रहे हैं।

सू- दोकू क्र.057

	2		6		8		3	
9		8		3		4		
							5	
5		2			7		6	
	8		4			1		3
				9				
8			9				1	
	5			1		6		2
		1	7				4	

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र. 56 का हल

2	6	3	8	1	4	9	7	5
9	5	4	2	6	7	3	1	8
8	7	1	9	3	5		6	2
6	2	7	5	4	8	4	3	9
3	9	8	6	7	1	2	5	4
4	1	5	3	2	9	6	8	7
5	3	2	4	8	6	7	9	1
1	8	6	7	9	2	5	4	3
7	4	9	1	5	3	8	2	6

शिक्षा के क्षेत्र में नई दूरियां

भारत डोगरा

इस वर्ष के केंद्र सरकार के आम बजट में शिक्षा के बजट में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2०19-2० में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बजट 94854 करोड़ रुपये का था, जबकि 2०19-2० के बजट में 99312 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस वृद्धि का स्वागत किया गया है, पर यदि हम इस बजट को और नजदीकी से देखें तो इसमें अनेक नई समस्याएं भी उभरती नजर आती हैं।

चिंता की एक बात तो यह है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बजट में बहुत कमी आई है। पूर्व की तुलना में बजटीय प्रावधान बेकल कर देने वाले हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान राज्यों के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को सुधारने की केंद्र सरकार की मुख्य स्कीम रही है। इसके लिए वर्ष 2०19-2० का बजट अनुमान 21०० करोड़ रुपये था पर वित्तीय वर्ष 2०2०-21 के बजट अनुमान को मात्र 3०० करोड़ रुपये रखा गया है। यकीनन बजटीय प्रावधान में इस कटौती से उच्चतर शिक्षा में बहुत कठिनाई हो सकती है, विशेषकर यह ध्यान में रखते हुए कि पिछले वर्ष भी इस अभियान में कटौती की गई थी। जहां मूल प्रावधान 21०० करोड़ रुपये का था, वहां संशोधित अनुमान में इसे घटा कर 138० करोड़ रुपये कर दिया गया था। जहां इस पूरे अभियान में कटौती हुई है, वहां कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना और कठिन हो गया है। इस अभियान में अनुसूचित जातियों के लिए 412 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। यह अब सिमट कर 5० करोड़ रुपये पर पंहुच गई है। इस अभियान में अनुसूचित जन-जातियों के लिए 2०19-2० में 222 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी (बजट अनुमान)। यह 2०2०-21 के बजट अनुमान में 25 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। इन दोनों समुदायों के लिए उच्च शिक्षा विभाग की छात्रवृत्तियों में भी कमी आई है।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही एक चर्चित स्कीम रही है। इसके लिए वर्ष 2०19-2० में 28० करोड़ रुपये का प्रावधान था, जबकि 2०2०-21 में इसे कम करके 22० करोड़ रुपये कर दिया गया है। वैसे, पिछले वर्ष के प्रावधान को भी सिमटा कर संशोधित अनुमान में 2०० करोड़ रुपये कर दिया गया था। अनुसूचित जातियों के छात्रों और छात्राओं के होस्टल के लिए वर्ष 2०19-2० में 53 करोड़ रुपये का मूल प्रावधान था जबकि वर्ष 2०2०-21 में इसके लिए मात्र 15 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस तरह के तमाम उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मूल प्रावधान में 5 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद शिक्षा क्षेत्र की अनेक महत्त्वपूर्ण स्कीमों के लिए संसाधनों में महत्त्वपूर्ण कमी आ सकती है, और इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए कि इस संसाधनों की कमी का सामना कैसे किया जाए। ऐसे में बेहतर तो यही होगा कि सरकार स्वयं संशोधित अनुमान में वृद्धि करके इस कमी को पूरा करे। एक अन्य चिंता की बात यह है कि शिक्षा का बजट उपकर या सेस पर बहुत अधिक निर्भर होता जा रहा है।

इस वर्ष का अनुमान है कि समग्र शिक्षा अभियान का लगभग तीन-चौथाई बजट शिक्षा उपकर से प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के कुछ अन्य पक्षों के बजट को विनिवेश प्रक्रिया पर निर्भर किया जा रहा है। विशेषकर केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के आंवटन को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर और पेट्रोल और डीजल के उपकर पर निर्भर होना पड़ रहा है। महत्त्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं के लिए बजट की अपनी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए कि यदि किसी कारण सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेश रोकना जरूरी समझा जाए तो इससे शिक्षा का जरूरी बजट ही खतरे में पड़ जाए। जहां शिक्षा में विभिन्न सुधारों की बात की जाती है वहां बजट में इसके अनुकूल वृद्धि भी होनी चाहिए।